रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 10 जुलाई, 1985/19 आषाढ़, 1907

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 4 जुलाई, 1985

संख्या 1-43/84-वि०स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1985 (1985 का विधेयक संख्यांक 4) जो दिनांक 4 जुलाई, 1985 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो गया है, सर्व साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

विश्वेश्वर वर्मा,
सचिव।

1411-राजपत्र/85-10-7-85—1,149.

मूल्य: 20 पैसे।

1985 का विधेयक संख्यांक 4.

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1985

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धन राशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक ।

भारतीय गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1985 है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से 1985-86 वर्ष के लिए 6,76,84,07,000 रुपए की राशि जारी करना ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धन राशियां जिनका योग हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1985 और हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1985 की अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में विनिर्दिष्ट धन राशियों को मिलाकर छः अरब, छहत्तर करोड़, चौरासी लाख, सात हजार रुपए है संदत्त और उपयोजित की जाए जिनका वित्तीय वर्ष 1985-86 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में निर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाए । 1985 का 2 1985 का 3

विनियोग ।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित करने के लिए प्राधिकृत धन राशियों का इस अधिनियम की धारा 2 में उल्लिखित अवधि के सम्बन्ध में अभिव्यक्त प्रयोजनों और सेवाओं के लिए विनियोग किया जायगा ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

मांग संख्या	सेवाएं एवं प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों का अधिक		
			विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
1	2		3		4
			रुपये	रुपये	रुपये
1	विधान सभा तथा निर्वाचन	(राजस्व)	1,28,23,000	1,70,000	1,29,93,000
2	राज्यपाल तथा मन्त्रि परिषद्	(राजस्व)	50,39,000	21,00,000	71,39,000
3	न्याय प्रशासन	(राजस्व)	1,98,11,000	58,41,000	2,56,52,000
4	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	12,75,53,000	28,18,000	13,03,71,000
		(पूंजी)	2,90,000	—	2,90,000
5	भू-राजस्व	(राजस्व)	7,52,39,000	—	7,52,39,000
		(पूंजी)	9,00,000	—	9,00,000
6	आबकारी तथा कराधान	(राजस्व)	2,46,34,000	—	2,46,34,000
7	पुलिस तथा अग्नि सुरक्षा	(राजस्व)	16,01,50,000	—	16,01,50,000
8	शिक्षा, कला तथा संस्कृति एवं वैज्ञानिक अनुसंधान	(राजस्व)	73,14,52,000	—	73,14,52,000
		(पूंजी)	2,18,14,000	—	2,18,14,000
9	चिकित्सा और परिवार नियोजन	(राजस्व)	25,71,04,000	—	25,71,04,000
		(पूंजी)	2,62,70,000	—	2,62,70,000
10	लोक निर्माण	(राजस्व)	34,91,76,000	—	34,91,76,000
		(पूंजी)	2,94,04,000	—	2,94,04,000
11	कृषि	(राजस्व)	20,49,06,000	—	20,49,06,000
		(पूंजी)	8,14,19,000	—	8,14,19,000
12	लघु सिंचाई	(राजस्व)	10,89,55,000	—	10,89,55,000
		(पूंजी)	2,73,83,000	—	2,73,83,000
13	भूमि तथा जल संरक्षण	(राजस्व)	6,73,77,000	—	6,73,77,000
		(पूंजी)	34,85,000	—	34,85,000
14	पशुपालन तथा दुग्ध विकास	(राजस्व)	6,62,36,000	30,000	6,62,66,000
		(पूंजी)	85,82,000	—	85,82,000
15	मत्स्य	(राजस्व)	68,17,000	—	68,17,000
		(पूंजी)	34,15,000	—	34,15,000
16	वन	(राजस्व)	19,40,53,000	—	19,40,53,000
		(पूंजी)	1,63,00,000	—	1,63,00,000
17	सड़कें तथा पुल	(राजस्व)	11,24,00,000	—	11,24,00,000
		(पूंजी)	29,01,22,000	2,66,000	29,03,88,000
18	सप्लाई, उद्योग तथा खनिज	(राजस्व)	10,24,37,000	—	10,24,37,000
		(पूंजी)	2,00,69,000	—	2,00,69,000

1	2		3		4
			रुपये	रुपये	रुपये
19	सामाजिक सुरक्षा, कल्याण तथा जेलें	(राजस्व)	9,58,29,000	—	9,58,29,000
		(पूंजी)	59,40,000	—	59,40,000
20	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	(राजस्व)	29,91,76,000	—	29,91,76,000
		(पूंजी)	11,49,68,000	—	11,49,68,000
21	सामुदायिक विकास	(राजस्व)	20,40,29,000	26,000	20,40,55,000
		(पूंजी)	3,85,000	—	3,85,000
22	सहकारिता	(राजस्व)	3,76,06,000	—	3,76,06,000
		(पूंजी)	3,79,77,000	—	3,79,77,000
23	खाद्य एवं पोषाहार	(राजस्व)	3,56,04,000	—	3,56,04,000
		(पूंजी)	8,75,57,000	—	8,75,57,000
24	जल तथा विद्युत विकास	(राजस्व)	1,72,00,000	—	1,72,00,000
		(पूंजी)	43,12,08,000	—	43,12,08,000
25	सिंचाई, नावचालन, जल निकास तथा बाढ़ नियन्त्रण	(राजस्व)	1,70,00,000	—	1,70,00,000
		(पूंजी)	2,18,95,000	—	2,18,95,000
26	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	(राजस्व)	2,22,78,000	—	2,22,78,000
		(पूंजी)	55,00,000	—	55,00,000
27	सड़क परिवहन	(राजस्व)	40,18,000	—	40,18,000
		(पूंजी)	1,94,72,000	—	1,94,72,000
28	पर्यटन	(राजस्व)	49,37,000	—	49,37,000
		(पूंजी)	79,70,000	—	79,70,000
29	श्रम तथा रोजगार	(राजस्व)	1,87,18,000	—	1,87,18,000
		(पूंजी)	17,62,000	—	17,62,000
30	आवास	(राजस्व)	1,41,94,000	—	1,41,94,000
		(पूंजी)	2,35,87,000	—	2,35,87,000
31	नगर विकास	(राजस्व)	4,08,40,000	—	4,08,40,000
		(पूंजी)	63,55,000	—	63,55,000
32	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	(राजस्व)	11,74,76,000	—	11,74,76,000
		(पूंजी)	79,81,000	—	79,81,000
33	वित्त	(राजस्व)	12,84,69,000	34,69,92,000	47,54,61,000
		(पूंजी)	—	1,02,28,50,000	1,02,28,50,000
34	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	(पूंजी)	3,19,00,000	—	3,19,00,000
35	जनजातीय विकास	(राजस्व)	26,20,80,000	—	26,20,80,000
		(पूंजी)	10,77,88,000	—	10,77,88,000
	कुल जोड़	. .	5,38,73,14,000	1,38,10,93,000	6,76,84,07,000

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खंड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधी में से वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध, संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए हिमाचल राज्य की संचित निधि में से अपक्षित धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
जुलाई 4, 1985

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग फाइल संख्या फिन-ए-सी (1) 26/84-II)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के विनियोग विधेयक, 1985 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को, विधान सभा में पुरःस्थापित और विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

[*Authorised English Text of the Himachal Pradesh Viniyog Vidhaik*, 1985 (1985 *ka Vidhaik Sankhayank* 4) *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

Bill No. 4 of 1985.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 1985

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year 1985-86.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Act, 1985.

Issue of sum of Rs. 6,76,84,07,000 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the year 1985-86.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate, inclusive of sums specified in column (3) of the Schedule to the Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1985 and Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act 1985 to the sum of six hundred seventy six crore, eighty four lakh, seven thousand rupees, (Rs. 6,76,84,07,000) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 1985-86 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule. 2 of 1985 3 of 1985

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period mentioned in section 2 of this Act.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

Demand No.	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by Legislative Assembly	*Charged* on the Consolidated Fund	Total
1	2		3		4
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha and Elections	(Revenue)	1,28,23,000	1,70,000	1,29,93,000
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	50,39,000	21,00,000	71,39,000
3	Administration of Justice	(Revenue)	1,98,11,000	58,41,000	2,56,52,000
4	General Administration	(Revenue)	12,75,53,000	28,18,000	13,03,71,000
		(Capital)	2,90,000	—	2,90,000
5	Land Revenue	(Revenue)	7,52,39,000	—	7,52,39,000
		(Capital)	9,00,000	—	9,00,000
6	Excise and Taxation	(Revenue)	2,46,34,000	—	2,46,34,000
7	Police and Fire Protection	(Revenue)	16,01,50,000	—	16,01,50,000
8	Education, Art and Cultural Affairs and Scientific Research	(Revenue)	73,14,52,000	—	73,14,52,000
		(Capital)	2,18,14,000	—	2,18,14,000
9	Medical and Family Planning	(Revenue)	25,71,04,000	—	25,71,04,000
		(Capital)	2,62,70,000	—	2,62,70,000
10	Public Works	(Revenue)	34,91,76,000	—	34,91,76,000
		(Capital)	2,94,04,000	—	2,94,04,000
11	Agriculture	(Revenue)	20,49,06,000	—	20,49,06,000
		(Capital)	8,14,19,000	—	8,14,19,000
12	Minor Irrigation	(Revenue)	10,89,55,000	—	10,89,55,000
		(Capital)	2,73,83,000	—	2,73,83,000
13	Soil and Water Conservation	(Revenue)	6,73,77,000	—	6,73,77,000
		(Capital)	34,85,000	—	34,85,000
14	Animal Husbandry and Dairy Development	(Revenue)	6,62,36,000	30,000	6,62,66,000
		(Capital)	85,82,000	—	85,82,000
15	Fisheries	(Revenue)	68,17,000	—	68,17,000
		(Capital)	34,15,000	—	34,15,000
16	Forest	(Revenue)	19,40,53,000	—	19,40,53,000
		(Capital)	1,63,00,000	—	1,63,00,000
17	Roads and Bridges	(Revenue)	11,24,00,000	—	11,24,00,000
		(Capital)	29,01,22,000	2,66,000	29,03,88,000
18	Supplies, Industries and Minerals	(Revenue)	10,24,37,000	—	10,24,37,000
		(Capital)	2,00,69,000	—	2,00,69,000
19	Social Security, Welfare and Jails	(Revenue)	9,58,29,000	—	9,58,29,000
		Capital)	59,40,000	—	59,40,000
20	Public Health, Sanitation and Water Supply	(Revenue)	29,91,76,000	—	29,91,76,000
		Capital)	11,49,68,000	—	11,49,68,000
21	Community Development	(Revenue)	20,40,29,000	26,000	20,40,55,000
		(Capital)	3,85,000	—	3,85,000
22	Co-operation	(Revenue)	3,76,06,000	—	3,76,06,000
		(Capital)	3,79,77,000	—	3,79,77,000

Demand No.	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by Legislative Assembly	*Charged* on the Consolidated Fund	Total
1	2			3	4
			Rs.	Rs.	Rs.
23	Food and Nutrition	(Revenue)	3,56,04,000	—	3,56,04,000
		(Capital)	8,75,57,000	—	8,75,57,000
24	Water and Power Development	(Revenue)	1,72,00,000	—	1,72,00,000
		(Capital)	43,12,08,000	—	43,12,08,000
25	Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control	(Revenue)	1,70,00,000	—	1,70,00,000
		(Capital)	2,18,95,000	—	2,18,95,000
26	Stationery and Printing	(Revenue)	2,22,78,000	—	2,22,78,000
		(Capital)	55,00,000	—	55,00,000
27	Road Transport	(Revenue)	40,18,000	—	40,18,000
		(Capital)	1,94,72,000	—	1,94,72,000
28	Tourism	(Revenue)	49,37,000	—	49,37,000
		(Capital)	79,70,000	—	79,70,000
29	Labour and Employment	(Revenue)	1,87,18,000	—	1,87,18,000
		(Capital)	17,62,000	—	17,62,000
30	Housing	(Revenue)	1,41,94,000	—	1,41,94,000
		(Capital)	2,35,87,000	—	2,35,87,000
31	Urban Development	(Revenue)	4,08,40,000	—	4,08,40,000
		(Capital)	63,55,000	—	63,55,000
32	Other Administrative Services	(Revenue)	11,74,76,000	—	11,74,76,000
		(Capital)	79,81,000	—	79,81,000
33	Finance	(Revenue)	12,84,69,000	34,69,92,000	47,54,61,000
		(Capital)	—	1,02,28,50,000	1,02,28,50,000
34	Loans to Government Servants	(Capital)	3,19,00,000	—	3,19,00,000
35	Tribal Development	(Revenue)	26,20,80,000	—	26,20,80,000
		(Capital)	10,77,88,000	—	10,77,88,000
	Grand Total	..	5,38,73,14,000	1,38,10,93,000	6,76,84,07,000

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 of the Constitution of India, to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year, 1985-86.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :
The 4th July, 1985

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. A.C(1)26/84-Vol. II]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the proposed Himachal Pradesh Appropriation Bill, 1985 recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction in, and consideration by, the Legislative Assembly of the said Bill.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।